



13 मिनट	8	23	1	GS1 • 1	GS2 • 15	GS3 • 15
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	मेन्स प्रश्न	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 SEBI कंपनियों को अनुमति देने की योजना बना रहा है

क्यों जरूरी: SEBI निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और जारीकर्ताओं के लिए लागत कम करने हेतु SME प्लेटफॉर्म IPOs के लिए कंपनियों की पात्रता का विस्तार करने का प्रस्ताव कर रहा है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

2 खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रीय खनिज विकास और संसाधनों पर संघीय अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था

क्यों जरूरी: खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रीय खनिज विकास और संसाधनों पर संघीय अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

GS2 • शासन

P

M

3 केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया

क्यों जरूरी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' की जांच हेतु इसे एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

4 भारत के Defence Ministry ने मांगा Rs 1 Lakh Crore का Aircraft Deal, घरेलू मेकर्स को प्राथमिकता

क्यों जरूरी: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देने के लिए विमानों की व्यापक खरीद हेतु सूचना के अनुरोध (RFIs) जारी किए हैं।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

5 Strait of Hormuz में Iran और US के बीच टकराव; जलडमरूमध्य खोलने के लिए बातचीत

क्यों जरूरी: होरमुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और US के बीच उत्पन्न गतिरोध, समुद्री सुरक्षा से संबंधित भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को रेखांकित करता है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

पृ.2 मुख्य खबरें » संक्षेप में » अभ्यास

P = प्रीलिम्स • M = मेन्स

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

SEBI कंपनियों को अनुमति देने की योजना बना रहा है

चर्चा में क्यों: SEBI निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और जारीकर्ताओं के लिए लागत कम करने हेतु SME प्लेटफॉर्म IPOs के लिए कंपनियों की पात्रता का विस्तार करने का प्रस्ताव कर रहा है।

याद रखें

- SEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- SME प्लेटफॉर्म IPOs के लिए प्रस्तावित बाजार मूल्य सीमा: Rs 4,000 करोड़।
- SME प्लेटफॉर्म IPOs के लिए वर्तमान बाजार मूल्य सीमा: Rs 5 billion।

मेन्स कोण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए आईपीओ (IPO) प्रक्रिया को सरल बनाना किस प्रकार भारतीय पूंजी बाजारों को गहरा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103012

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया

चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' की जांच हेतु इसे एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया।

याद रखें

- संयुक्त संसदीय समिति (JPC): भारतीय संसद की एक समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं।
- Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA): व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानून।
- अमित शाह: भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री।

मेन्स कोण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी वित्तपोषण को प्रभावित करने वाले विधानों में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जांच सुनिश्चित करने में संयुक्त संसदीय समिति के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103272

GS2 · शासन

P

M

खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रीय खनिज विकास और संसाधनों पर संघीय अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था

चर्चा में क्यों: खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रीय खनिज विकास और संसाधनों पर संघीय अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

याद रखें

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
- यह संशोधन केवल प्रमुख खनिजों (major minerals) पर लागू होता है; लघु खनिज (minor minerals) राज्य के नियंत्रण में बने रहेंगे।
- जी. किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं।

मेन्स कोण भारत में औद्योगिक विकास और संघवाद के बीच संतुलन स्थापित करने में 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103400

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

भारत के Defence Ministry ने मांगा Rs 1 Lakh Crore का Aircraft Deal, घरेलू मेकर्स को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देने के लिए विमानों की व्यापक खरीद हेतु सूचना के अनुरोध (RFIs) जारी किए हैं।

याद रखें

- मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद का मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है।
- प्रशिक्षण विमानों की खरीद का मूल्य लगभग Rs 15,000 करोड़ है।
- HAL (Hindustan Aeronautics Limited) भारत की एक प्रमुख राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण कंपनी है।

मेन्स कोण बड़े पैमाने पर रक्षा खरीद में घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और औद्योगिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है, चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103240

Strait of Hormuz में Iran और US के बीच टकराव; जलडमरूमध्य खोलने के लिए बातचीत

चर्चा में क्यों: होरमुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और US के बीच उत्पन्न गतिरोध, समुद्री सुरक्षा से संबंधित भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को रेखांकित करता है।

याद रखें

- हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- ईरान ने अपनी मांगों के हिस्से के रूप में अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की है।
- ओमान और पाकिस्तान वर्तमान में जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और शांति वार्ता की सुविधा प्रदान करने के लिए मध्यस्थता प्रयासों में शामिल हैं।

मेन्स कोण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समुद्री नाकाबंदी के निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103224

सुप्रीम कोर्ट 2026 में प्रेस फ्रीडम बनाम लेजिस्लेटिव प्रिविलेज पर 2003 का केस सुनेगा

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय हेतु सात न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठगठित की है कि क्या विधायी विशेषाधिकार अभिव्यक्ति और भाषण की मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रभावी हो सकते हैं।

याद रखें

- अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ में कम से कम पांच न्यायाधीश होते हैं।
- कानूनी जटिलता के कारण, इस मामले को दिसंबर 2004 में सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया था।

मेन्स कोण संसदीय/विधायी विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मध्य अंतर्निहित संघर्ष का परीक्षण कीजिए। क्या विशेषाधिकारों का उपयोग लोकतांत्रिक असहमति को सीमित करने के लिए किया जा सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103099

UN रिपोर्ट ने लाल किले विस्फोट के लिए AQIS को जिम्मेदार ठहराया

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने लाल किले में हुए घातक विस्फोट का उत्तरदायित्व अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) को दिया है, जो क्षेत्रीय आतंकवाद की बदलती रणनीतियों को रेखांकित करती है।

याद रखें

- लाल किला: पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला और एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल।
- AQIS: Al-Qaeda in the Indian Subcontinent, Al-Qaeda की एक क्षेत्रीय संबद्ध इकाई।
- UN Security Council: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार UN का प्राथमिक अंग।

मेन्स कोण AQIS जैसे क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों की विकसित होती कार्यप्रणालियों और दक्षिण एशिया में आंतरिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103214

स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रगान से पहले बजाया गया वंदे मातरम

चर्चा में क्यों: एक नए संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने यह अधिदेश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' गाया जाएगा।

याद रखें

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (2026 में संशोधित)।
- वन्दे मातरम् की अवधि: लगभग 3 मिनट 10 सेकंड।
- वन्दे मातरम् को 2026 में अपनी 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाएगा।

मेन्स कोण भारत की विविध आबादी के बीच सामूहिक पहचान और एकता की भावना को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/103088

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संसद ने खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो खनिज अधिकारों पर राज्यों की कराधान शक्तियों को प्रभावित करता है

BCI ने NALSAR 2026 के ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगाने का फैसला वापस लिया

राजस्थान कैबिनेट ने समान विरासत अधिकार और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए Uniform Civil Code बिल को मंजूरी दी

कर्नाटक ने लॉन्च किया Tathyakosh.in: आसान एक्सेस के लिए 1.5 मिलियन डेटासेट्स को किया एक साथ जोड़ना

केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को पलटा, NGOs पर गलत इस्तेमाल के आरोप हटाए

केरल हाई कोर्ट ने जेकोबाइट अपील खारिज की, मध्यस्थता से चर्च विवाद खत्म होने की उम्मीद

तमिलनाडु का दावा: कर्नाटक ने जबरन दिया पानी, स्वेच्छा से नहीं

केरल हाई कोर्ट में मामलों के निपटारे में भारी बढ़ोतरी

DDA की नई पॉलिसी: पुराने घर के मालिक मास्टर प्लान नियमों के तहत तोड़कर दोबारा बना सकेंगे घर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था वाली बलात्कार की उत्तरजीवी महिलाओं के लिए गर्भपात हेतु न्यायालय की अनुमति...

स्वास्थ्य मंत्री ने ऑपरेशन Soundarya में ₹9.64 लाख के नकली कॉस्मेटिक्स जब्त करने की घोषणा की

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

जून 14, 2024 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 19.4% हुई

बंगलुरु में रेजिडेंशियल पार्किंग पर लगेगा ₹25,000 तक का चार्ज

वर्ल्ड एलीफेंट डे पर आंध्र प्रदेश डिप्टी CM ने इंसान और हाथियों के सह-अस्तित्व की अपील की

Larsen & Toubro को चेन्नई में Rs 10,000-15,000 करोड़ की AI फैसिलिटी का ऑर्डर मिला

T-Hub ने deep tech के लिए 12 महीने का Blueprint फेलोशिप लॉन्च किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मल्ल्या के 9,000 करोड़ के बैंक विवाद को खत्म करने पर जोर दिया

बिहार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मंत्री राम कृपाल यादव ने बुधवार (August 12) को घोषणा की

अडानी ने आंध्र प्रदेश में ₹16,000 करोड़ के टाइटेनियम प्लांट का प्रस्ताव दिया

ILO: युवाओं की बेरोजगारी 12.4% पहुंची, COVID-19 के बाद NEET रेट बढ़कर 20% हुआ

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बलों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुनियादी ढाँचे के विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी-संवेदनशील...

Bank of America खरीदेगा Jio Credit में 49.9% तक का हिस्सा

GS3 • अर्थव्यवस्था

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए आईपीओ (IPO) प्रक्रिया को सरल बनाना किस प्रकार भारतीय पूंजी बाजारों को गहरा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।